



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2005/माघ 4, 1926

No. 21]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2005/MAGHA 4, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

विषय : गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली निवेश की पद्धति।

सं. फा. 5(53)/2002-ई.सी.बी. एण्ड पी.आर.— इस मंत्रालय की दिनांक 6 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. एफ.5(18)-ईसीबी/2001 के आंशिक संशोधन में गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा वृद्धिकारी आय के लिए निवेश संबंधी निवेश की पद्धति दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से निम्नानुसार होगी:-

निवेश पद्धति

निवेश की
जाने वाली
प्रतिशत राशि

- (i) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा-परिभाषित केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां; और/अथवा ऐसे म्यूचुअल फण्डों ; जिन्हें सरकारों प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित किया गया है, की यूनिटें ; 25%
- (ii) (क) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा-परिभाषित किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी सरकारी प्रतिभूतियों और/ अथवा ऐसे म्यूचुअल फण्डों, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित किया गया है, की यूनिटें और/अथवा 15%

(ख) अन्य कोई परक्राम्य प्रतिभूतियां जिनकी मूल राशि और जिन पर ब्याज नीचे (iii)(क) के अधीन शामिल को छोड़कर केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा किसी शर्त के बिना और पूर्णतः गारंटी शुदा है।

बशर्तेकि ऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित निवेश के अनुपात को ध्यान में न रखते हुए किसी भी एकल म्यूच्युअल फंड के संबंध में किसी न्यास (ट्रस्ट) का ऋण जोखिम जिसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधि के रूप में स्थापित किया गया है, किसी भी समय पर इसके कुल पोर्ट-फोलियो का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) न्यासी, अपने जोखिम प्राप्ति की संभावनाओं के निर्धारण के अधीन, यदि वे ऐसा निर्णय लें तो, ऊपर (i) और (ii) क वर्गों के तहत कुल पोर्टफोलियो को विक्रेय और गैर-विक्रेय वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में कुल पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत तक को विक्रेय के रूप में माना जा सकता है, और उसे सक्रिय प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

बशर्तेकि सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रेय पोर्टफोलियो को बाजार तथा म्यूच्युअल फंड के संबंध में चिन्हित किया जाएगा और जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है, को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निवल परिसंपत्ति मूल्य पर आंका जाएगा।

- (iii) (क) कम्पनी अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट “सरकारी वित्तीय संस्थाओं” ; सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (36-क) में यथापरिभाषित “सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों” के बाण्ड/प्रतिभूतियां ; और अथवा
(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी तीन वर्ष तक की सावाधे जमा प्राप्तेयां ।

बशर्तेकि ऊपर (iii)(क) के अंतर्गत शामिल किए गए लिखतों में कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त हों 25%

(ग) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा जारी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक उधार तथा ऋण बाध्यता (सीबीएलओ)

- (iv) उनके न्यासियों द्वारा जैसा निर्णय किया जाए उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक में निवेश। 30%
- (v) ऐसे कंपनियों के शेयर, जिनके पास कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड ऋण रेटिंग प्राप्त हो। 5%
- (vi) न्यास, जोखिम-प्राप्ति सम्भावनाओं के उनके निर्धारण के अधीन ऊपर (iv) में से एक तिहाई तक निजी क्षेत्र के ऋण लिखतों में, जिनके पास कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त हो और/अथवा भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूच्युअल फंडों की इक्विटी संबद्ध योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

अनिवार्य व्यय को घटाकर पूर्व निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी राशि इस अधिसूचना में निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश की जाएगी।

ऊपर उल्लिखित, किसी लिखत की रेटिंग किए जाने तथा उनकी रेटिंग के निवेश ग्रेड से नीचे होने तथा दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा इसी रेटिंग की पुष्टि किए जाने के मामले में निकारी विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।

4. उपरोक्त पैराग्राफों में यथासंस्कृत निवेश पद्धति वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त की जा सकती है।

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2005

Subject : Pattern of investment to be followed by non-Government Provident Funds, Superannuation Funds and Gratuity Funds.

No. F. 5(53)/2002-ECB & PR.— In partial modification of this Ministry's Notification Number 5(18)ECB/2001 dated 6th March 2003, the investment pattern for investment of incremental accretions by non-Government Provident Funds, Superannuation Funds and Gratuity Funds shall be as follows, effective from 1st April 2005:-

INVESTMENT PATTERN

	Percentage amount to be invested
(i) Central Government securities as defined in Sec. 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944); and/or units of such mutual funds which have been set up as dedicated funds for investment in Government securities and which are regulated by the Securities and Exchange Board of India;	25%
(ii) (a) Government securities as defined in Sec. 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944); created and issued by any State Government; and/or units of such mutual funds which have been set up as dedicated funds for investment in Government securities and which are regulated by the Securities and Exchange Board of India; and/or	15%
(b) Any other negotiable securities the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government except those covered under (iii) (a) below	

Provided that irrespective of the proportion of investments stated in (i) and (ii) above, exposure of a trust to any individual mutual fund which has been set up as a dedicated fund for investment in Government securities, should not be more than 5% of its total portfolio at any point of time.

(c) The Trustees, subject to their assessment of the risk-return prospects, may, if they so decide, divide the total portfolio under categories (i) and (ii)(a) above into tradable and non-tradable categories. Upto 10% of the total portfolio at the end of the preceding financial year can be treated as tradable and may be used for active management:

Provided that the tradable portfolio of Government securities shall be marked to market and mutual funds, which have been set up as dedicated funds for investment in Government securities, shall be valued at Net Asset Value at the close of the financial year.

- (iii) (a) Bonds/Securities of 'Public Financial Institutions' as specified under Section 4(1) of the Companies Act; "public sector companies" as defined in Section 2(36-A) of the Income Tax Act, 1961 including public sector banks; and/or

(b) Term Deposit Receipts upto three years issued by public sector banks

25%

Provided that the instruments covered under (iii) (a) above have an investment grade rating from at least two credit rating agencies.

(c) Collateral Borrowing and Lending Obligation (CBLO) issued by Clearing Corporation of India Limited and approved by the Reserve Bank of India.

- (iv) To be invested in any of the above three categories as decided by their Trustees.

30%

- (v) Shares of companies that have an investment grade debt rating from at least two credit rating agencies.

5%

- (vi) The Trustees, subject to their assessment of the risk-return prospects, may invest upto 1/3rd of (iv) above, in private sector debt instruments which have an investment grade rating from at least two credit rating agencies and/or in

equity-linked schemes of mutual funds regulated by the Securities and Exchange Board of India.

2. Any moneys received on the maturity of earlier investments reduced by obligatory outgoing shall be invested in accordance with the investment pattern prescribed in this notification.
3. In case of any instruments mentioned above being rated and their rating falling below investment grade and the same rating has been confirmed by two credit rating agencies then the option of exit can be exercised.
4. The investment pattern as envisaged in the above paragraphs may be achieved by the end of a financial year.

U. K. SINHA, Jt. Secy.

254 GI/05-2